शाम सुंदर

बनाम

पूरन और अन्य

सितंबर 21,1990

[न्यायाधिपति एस. रत्नवेल पांडियान और न्यायाधिपति एम. फातिमा बीवी]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 302,304 भाग-I-दोषसिद्धि-आजीवन कारावास-दूसरी अपील-धारा 304 भाग I के तहत एक में परिवर्तित और सजा को कम किया गया-कोई विशेष कारण नहीं दिया गया-दोषसिद्धि की वैधता-सजा-क्या पर्याप्त है।

वाक्य: सज़ा देना - प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए -सज़ा का माप अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।

प्रतिवादी 1, प्रतिवादी क्रमांक 2 का पुत्र है, प्रतिवादी क्रमांक 1 सहित प्रतिवादी क्रमांक 2 के 4 पुत्र थे। प्रतिवादी नंबर 2 के पास एक पी के गेहूं के खेत से सटे एक गन्ने का खेत था। प्रतिवादी -2 के बेटों में से एक ने गन्ने की फसल को जला दिया था, जिससे पी की गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था, जिसके खिलाफ पी ने उत्तरदाताओं के सामने विरोध किया था। विरोध ठुकरा दिया गया. इसके तुरंत बाद प्रतिवादी और परिवार के सदस्य पी के घर पहुंचे, वे सभी हथियारों से लैस थे। उत्तरदाताओं ने पी पर हमला

किया और वह गिर गया। अस्पताल ले जाते समय पी की मृत्यु हो गई। अधिकांश आरोपियों के साथ-साथ पी के परिवार के सदस्यों को भी चोटें आईं। शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई। जांच के बाद अभियोजन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामला दायर किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दो चश्मदीद गवाह पेश किये गये। वे मृतक के रिश्तेदार थे और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 302 और धारा 323, 325 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। दोनों को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक को 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें अन्य अपराधों के लिए छह महीने से लेकर एक साल तक के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। अन्य आरोपियों को कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। प्रतिवादी ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत बड़े आरोप से बरी कर दिया और धारा 304 भाग- I के तहत दोषसिद्धि दर्ज की और आजीवन कारावास की सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर दिया, और जुर्माने की सजा को बढ़ा दिया। राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की गई। हालाँकि, शिकायत ने विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की।

अपील को खारिज कराते हुए न्यायालय ने आयोजित किया :

1. केवल इच्छुक गवाहों के ही साक्ष्य हैं जिनकी प्रवृत्ति बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की होती है और इसमें निर्दोष व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। अधिकांश आरोपियों को चोटें आई हैं और इसकी व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष के गवाह सच्चे विवरण के साथ आगे नहीं आए हैं। यह हाथापाई उत्तरदाताओं और परिवार के अन्य सदस्यों के आक्रामक रवैये के कारण हुई, जिन्होंने निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में सभी संभावनाओं में भाग लिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। हालाँकि, परिस्थितियाँ मृत्यु के कारण की पुष्टि नहीं करतीं और उत्तरदाताओं को यह समझा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। चोटों की प्रकृति से संकेत मिलता है कि वे प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और जानबूझकर पहुंचाई गई थीं। ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदाताओं का कृत्य स्पष्ट रूप से धारा 304 भाग-1, आईपीसी के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के लिए कोई ठोस या स्पष्ट कारण नहीं दिया है और जो भी कारण बताया गया है वह गलत है। यह उस व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयान के आधार पर है, जिसकी इस मामले में जांच नहीं की गई थी कि उच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निकाला है। हालांकि, आईपीसी की धारा 304 भाग- । के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है।

2. उच्च न्यायालय ने सज़ा को घटाकर पहले ही जेल में बिताई गई अवधि तक कर दिया है और जुर्माना बढ़ा दिया है। उत्तरदाताओं को केवल

छह महीने से कम की छोटी अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ी है और, इस तरह के गंभीर अपराध में, दी गई सजा अपर्याप्त है। हाई कोर्ट की ओर से ऐसी सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है. किसी विशेष अपराध के लिए सजा तय करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उन परिस्थितियों, जिनमें यह किया गया था, और "अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार-विमर्श की डिग्री" को ध्यान में रखना चाहिए। सजा की माप अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा इतनी गंभीर और पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि इसमें न्याय की विफलता शामिल है। सजा को बढ़ाकर पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास में से एक कर दिया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 195/1984।

आपराधिक अपील संख्या 425 डी.बी./1982 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.1982 से।

ओ. पी. सोनी, सुश्री कमलेश दत्ता और एस. के. सभरवाल अपीलार्थी के लिए।

उत्तरदाताओं के लिए यू. आर. ललित और उमा दत्ता।

महाबीर सिंह हरियाणा राज्य के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था -

न्यायाधिपति फातिमा बीवी:

प्रतिवादी पूरन और तारा चंद के साथ वेद, बलवान, धापन, जगदीश और लाल चंद पर प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या और अन्य को घायल करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत के समक्ष मुकदमा चलाया गया। विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 18.5.1972 के फैसले द्वारा इन उत्तरदाताओं को आईपीसी की धारा 302 और धारा 323, 325 के साथ धारा 149, आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को धारा 302 के तहत 500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। आईपीसी की धारा 148 के तहत एक साल के लिए कठोर कारावास ,धारा 325 के तहत एक साल के लिए कठोर कारावास और धारा 323 आईपीसी के तहत छह महीने के लिए कठोर कारावास, अन्य आरोपियों को छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और धारा 360/361, सीआरपीसी के तहत परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.11.1982 द्वारा अपील का निपटारा इस प्रकार किया:

> "माना जाता है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। झगड़ा दोनों पक्षों के खेतों की आम सीमा पर गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने जैसी एक बहुत ही मामूली बात पर हुआ था। अगर प्रताप सिंह की मृत्यु हो

जाती तो शायद इस विवाद को भुला दिया गया होता मृत्यु नहीं हुई। यहां तक कि जब किसी छोटी घटना पर कोई विवाद होता है, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों की ओर से मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कुछ प्रवृत्ति होती है। तीन-चश्मदीद गवाहों ने निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है, लेकिन जांच अधिकारी ने बयान दर्ज किया है। जांच रिपोर्ट बनाते समय एक पारस राम की रिपोर्ट कुछ अलग ही देती है विद्वान विचारण न्यायाधीश ने स्वयं पाया है कि गैरकानूनी जमावड़े का उद्देश्य मृतक की हत्या करना नहीं था। यह ठीक इसी कारण से है कि पांच आरोपियों को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया है और केवल दो आरोपियों, यानी पूरन और तारा चंद अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है, हम विवाद के विवरण और अजीबोगरीब में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। इस मामले की परिस्थितियाँ पूरन और तारा चंद अपीलकर्ताओं की सजा को धारा 304, भाग -1 आईपीसी के तहत इस आधार पर परिवर्तित करती हैं कि उस समय पारस राम द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए जब जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट बनाई थी। कुछ अलग-अलग संस्करण दिए गए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा पारस राम को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया

था। चूंकि पक्षों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हम आदेश देते हैं कि अपीलकर्ता पूरन और तारा चंद को जो सजा पहले ही मिल चुकी है, उन्हें न्याय मिलेगा। हालाँकि, उन्हें प्रत्येक को 12,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को पांच साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया है। पूरन और तारा चंद अपीलकर्ताओं को अन्य मामलों में दी गई कारावास की सजा भी कम कर दी गई है जो वे पहले ही भुगत चुके हैं। यदि कुल जुर्माना वसूल हो जाता है, तो मृतक प्रताप सिंह के अगले उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालय ने इस गुप्त आदेश द्वारा, उत्तरदाताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत प्रमुख आरोप से बरी कर दिया और धारा 304 भाग-1 के तहत उनकी दोषसिद्धि दर्ज की और आजीवन कारावास की सजा को कम करके पहले से ही कारावास की अवधि तक कम कर दिया, जबकि जुर्माने की सजा को बढ़ा दिया। राज्य ने बरी करने या सजा कम करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं ने निर्णय स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, वास्तविक

शिकायतकर्ता शाम सुंदर ने व्यथित होकर संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी है।

उच्च न्यायालय, किसी दोषसिद्धि की अपील में धारा 386, सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष और सजा को उलट सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है या सजा को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष में बदलाव कर सकता है या प्रकृति या सीमा के बाद निष्कर्ष में बदलाव के साथ या बिना बदलाव कर सकता है। सज़ा की प्रकृति और सीमा, लेकिन इतनी नहीं कि उसे बढ़ाया जा सके। सबूतों से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ विचारण न्यायालय जितनी ही व्यापक हैं। तथ्यों की अंतिम अदालत के रूप में, उच्च न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह सबूतों की जांच करे और रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसके समक्ष अपीलकर्ता दोषी हैं या अन्यथा।

यह सच है कि उच्च न्यायालय मामले में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है। यह भी सच है कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट आम तौर पर अपने लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है

यह निर्धारित करना कि उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है या नहीं तथ्यों पर निष्कर्ष लेकिन जहां उच्च न्यायालय ने निर्धारण की आवश्यकता वाले वास्तविक बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और गलत आधार पर साक्ष्य को भी खारिज कर दिया है और इस तथ्य

पर विचार करने में विफल रहा है कि पार्टियों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण इसमें शामिल होने की प्रवृत्ति है निर्दोष व्यक्तियों और घटना के संबंध में बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और पूर्व-न्यायालय का नेतृत्व करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से साक्ष्य में जाना उचित होगा कि मामले में गंभीर अन्याय नहीं हुआ है।

हमने यह इंगित करने के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा निकाला है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। सबूतों की कोई चर्चा नहीं है, किसी तर्क की तो बात ही छोड़िए। विचारण न्यायालय ने दो चश्मदीद गवाहों की गवाही और अभिलेख पर अन्य भौतिक साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए यहां उत्तरदाताओं को पांच अन्य लोगों के साथ दोषी पाया था।

तथ्यों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है लाल चंद और तारा चंद भाई हैं। वेद सिंह, पूरन, बलवान और ईश्वर तारा चंद के बेटे हैं और धापन उनकी पत्नी हैं, जगदीश लालचंद के बेटे हैं। प्रताप और भीम सिंह भाई हैं। शाम सुंदर भीम सिंह के बेटे हैं. रोशन, प्रताप का पुत्र है। तारा चंद के पास प्रताप के गेहूं के खेत से लगा हुआ गन्ने का खेत है। दिनांक 10.3.1981 को सुबह वेद सिंह ने गन्ने की फसल जला दी, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। रोशन द्वारा किये गये विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया. भीमसिंह मौके पर पहुंचे और विवाद शुरू हो गया। बाद में प्रताप ने तारा चंद के समक्ष विरोध जताया। उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया गया.

लगभग शाम 6.00 बजे प्रताप ने पूरन के समक्ष विरोध जताया जिसे उन्होंने भी ठुकरा दिया। इसके तुरंत बाद पूरन और उसके परिवार के अन्य सदस्य जिनमें उसकी पत्नी, भाई और उनके बच्चे शामिल थे, सभी लगभग आठ की संख्या में प्रताप के घर के सामने पहुँचे। वे हथियारों से लैस थे और उन्होंने प्रताप पर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रतिवादी तारा चंद और पूरण ने पहले तो प्रताप पर जेलियों से हमला कियाजेलियों ने शूल की ओर से सीने में वार किए और जब प्रताप गिर गए तो उन्होंने जेलियों को उनके सिर, पीठ और कंधे पर लाठियों से वार किया, प्रताप की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। आगे आरोप है कि घटना के दौरान लाल चंद और जगदीश ने रोशन को चोटें पहुंचाईं; ईश्वर ने प्रताप की पत्नी धापन को चोट पहुंचाई; पूरन, वेद, बलवान ने शाम सुंदर को चोटें पहुंचाईं। सबूत के तौर पर सामने आया है कि घटना के दौरान वेद, धापन, लाल चंद, पूरन और ईश्वर को भी चोटें आईं।

इसके अलावा शाम सुंदर और रोशन दो चश्मदीद गवाह हैंमृतक प्रताप की पत्नी श्रीमती धापन के पास कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, शाम सुंदर और रोशन ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में विपरीत पक्ष के सदस्यों को चोट पहुंचाई थी। हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। साक्ष्य घटना की उत्पत्ति का खुलासा नहीं करता है; यह कैसे विकसित हुआ और प्रताप को घातक चोटों के रूप में परिणत हुआ। दोनों समूहों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी. झगड़े

का तात्कालिक कारण गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचना है। माना जा रहा है कि प्रताप ने सुबह से लेकर मेडिकल कॉलेज, रोहतक के कर्मचारी पूरन के आने तक अपना विरोध जताया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने इसे तब मोड़ दिया जब वे कहते हैं कि शाम 6.00 बजे। प्रताप की मुलाकात पूरन से हुई जिसने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया और घर चला गया और 15 मिनट के बाद महिलाओं सहित उसके परिवार के सभी सदस्य प्रताप के घर पहुंचे और हमला शुरू कर दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों परिवारों की महिलाएं और यहां तक कि छोटे बच्चे भी उस स्थान पर मौजूद थे और उन्हें चोटें आईं। इसलिए यह अपील की जाएगी कि यह एक सतत लेन-देन था और जब प्रताप ने लगातार विरोध जताया और पूरन को गाली देना शुरू कर दिया, तो उसके घर के अन्य सदस्य बाहर आ गए। झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया था और आगे चलकर प्रताप को घातक चोटें आई थीं। उत्तरदाताओं की दलील थी कि उन्होंने कोई चोट नहीं पहुँचाई, वहाँ एक पंचायत थी जहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी और ईंट-पत्थरबाजी और विवाद हुआ था। निजी बचाव की दलील विशेष रूप से स्थापित नहीं की गई थी। हालाँकि, यदि साक्ष्य में यह संकेत देने वाली सामग्री है कि घटना चश्मदीदों द्वारा बताए गए तरीके से नहीं हुई होगी और पूरी संभावना है कि उत्तरदाताओं ने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए बल का प्रयोग किया था, तो आरोपी इसके हकदार हैं क्या उत्तरदाताओं ने ऐसी परिस्थितियों में अपने अधिकार का उल्लंघन किया है

और मृत्यु कारित करना उचित है, इस पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की पूर्ण चर्चा के अभाव में हम रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं। हमने देखा है कि केवल इच्छुक गवाहों के साक्ष्य हैं जिनमें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और निर्दोष व्यक्तियों को भी शामिल करने की प्रवृत्ति होती है। हमने देखा है कि अधिकांश अभियुक्तों को चोटें आई हैं और इसकी व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष के गवाह सच्चे बयान के साथ आगे नहीं आए हैं। हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया है कि प्रताप के आक्रामक रवैये के कारण हुई हाथापाई में, उत्तरदाताओं और परिवार के अन्य सदस्यों ने भाग लिया और निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में सभी संभावनाओं में प्रताप और उसके सहयोगियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया। हालाँकि, परिस्थितियाँ मृत्यु के कारण की गारंटी नहीं देतीं और उत्तरदाताओं को यह समझा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। चोटों की प्रकृति से संकेत मिलता है कि प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोटें जानबूझकर पहुंचाई गई थीं। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादियों का कृत्य पूरी तरह से आईपीसी की धारा 304 भाग-1 के अंतर्गत आता है। हालाँकि हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के लिए कोई ठोस या स्पष्ट कारण नहीं दिया है और जो भी कारण

हो गलत बताया गया है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयान के आधार पर, जिसकी मामले में जांच नहीं की गई थी, उच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निकाला है। हालाँकि, हम आईपीसी की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हैं।

उच्च न्यायालय ने जुर्माना बढ़ाते हुए सजा को घटाकर पहले ही काट ली गई कारावास की अवधि तक कर दिया है। यह बताया गया है कि उत्तरदाताओं को केवल छह महीने से कम अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ी है और, इस तरह के गंभीर अपराध में, दी गई सजा अपर्याप्त है। उच्च न्यायालय की ओर से ऐसी सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है. किसी विशेष अपराध के लिए सजा तय करते समय अदालत को अपराध की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में यह किया गया था, और अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार-विमर्श की डिग्री को ध्यान में रखना चाहिए। सज़ा का माप अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। सज़ा सुनाई गई. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अत्यधिक और पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होता है, जिसमें न्याय की विफलता शामिल है। हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सजा को बढ़ाना होगा।

परिणाम में हम उत्तरदाताओं के विश्वास को बरकरार रखते हैं लेकिन सज़ा को पाँच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास तक बढ़ाएँ। उत्तरदाताओं को सजा का शेष भाग भुगतने के लिए जमानत के लिए

आत्मसमर्पण करना चाहिए। यदि जुर्माना अदा कर दिया गया है, तो उत्तरदाताओं 1 और 2 को वापस कर दिया जाएगा।

अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

जी एन

अपील निस्तारित की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।